

[2023] 5 एस. सी. आर 682

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. और अन्य।

बनाम

एम/एस सत्यनारायण सर्विस स्टेशन और अन्य.

(2023 की सिविल अपील No.3533)

मई 09, 2023

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996: धारा 34 – मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन – अपीलकर्ता-आईओसी ने पहले प्रतिवादी के साथ पेट्रोल पंप डीलर समझौता किया – तीन साल के बाद, पहले प्रतिवादी ने डीलरशिप से हटने की मांग की और उक्त अनुरोध नोटरीकृत किया गया था, और उसके बाद अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया – इसके बाद, पहले प्रतिवादी ने डीलरशिप से इस्तीफा वापस लेने का इरादा व्यक्त किया, हालांकि, इसे स्वीकार नहीं किया गया – आईओसी ने पेट्रोलियम आउटलेट पर कब्जा कर लिया और नए डीलर को डीलरशिप प्रदान की गई – पहले प्रतिवादी ने इसे चुनौती दी – अपीलकर्ता के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार – पहले प्रतिवादी ने फिर धारा 34 के तहत मध्यस्थता मुकदमा दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया – हालांकि, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया और पहले प्रतिवादी को डीलरशिप बहाल करने का निर्देश दिया – अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ने गलती की पुरस्कार को रद्द करने के बाद पहले प्रतिवादी को डीलरशिप की बहाली का आदेश देने की कार्यवाही में और पहले प्रतिवादी को नुकसान का दावा करने के लिए खुला छोड़ कर – अदालत पुरस्कार को रद्द करने के बाद, पुरस्कार को संशोधित करके आगे राहत देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती – पहला प्रतिवादी वास्तव में लागू खंड (3) – खंड (3) डीलरशिप से इस्तीफे का प्रावधान नहीं करता है – यह केवल समझौते को समाप्त करने का प्रावधान करता है – पहले प्रतिवादी ने पत्र में संकेत दिया कि वह डीलरशिप से वापस ले रहा है – इस आधार पर आगे बढ़ना कि समय से पहले समझौते की समाप्ति के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी, मध्यस्थ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को विकृत नहीं माना जा सकता है – हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश को स्वीकार्य पाए गए मध्यस्थ के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अवैध रूप से काम किया, कि स्वीकृति थी, इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित:- **1.1** प्रथम प्रतिवादी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि डीलरशिप को समाप्त नहीं किया जा सकता है। डीलरशिप के पहले **15** वर्षों के दौरान तीन महीने का नोटिस देना। इस तरह की व्याख्या मध्यस्थ के विचार के लिए नहीं रखी गई थी। इसे जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया जाता है। पहला प्रतिवादी इस अधिनियम के तहत उत्पन्न एक मामले में इस न्यायालय से पूरी तरह से नई व्याख्या करने का आग्रह कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रचारित विवाद ही एकमात्र संभव दृश्य है। वास्तव में, पहले प्रतिवादी का आचरण व्याख्या पर आधारित

होता है जो पार्टियों को डीलरशिप के पहले **15** वर्षों के भीतर भी तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए खुला छोड़ देता है। [पैरा **18**][696-सीएफ]

1.2 खंड (3) के अवलोकन पर, वास्तव में, यह पता चला कि अनुबंध में एक शर्त होती है जिसमें स्पष्ट रूप से तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यह न्यायालय इस खंड को इस अर्थ में तोड़ देगा कि उसने समझौते को समाप्त करने के इरादे से दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष (अनुबंध से हटाए गए शब्द) द्वारा समझौते के निर्धारण पर विचार किया। खंड में प्रावधान है कि ऐसे नोटिस की समाप्ति पर, समझौता और दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। किसी नोटिस की स्वीकृति का संकेत देने वाले शब्द भी नहीं हैं समझौते के निर्धारण के लिए अपरिहार्य मानकर समझौते को समाप्त करने का इरादा। नोटिस जारी होने से गेंद घूमती है और प्रक्रिया सफलतापूर्वक समझौते में समाप्त होती दिखाई देती है और समझौते के तहत दिया गया लाइसेंस रद्द या रद्द कर दिया जाता है। [पैरा **19**][696-एफ-एच; 697-ए]

1.3 हालांकि इस तरह का दृष्टिकोण समझौते का सही निर्माण प्रतीत होता है, पहले प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले वकील का कहना है कि आईओसी और इससे भी अधिक, यहां तक कि मध्यस्थ, और इसलिए जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी इस पर आगे बढ़े हैं यह आधार कि केवल समाप्ति की सूचना की स्वीकृति ही पर्याप्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है, मामले पर इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि स्वीकृति आवश्यक है। [पैरा **20**][697-ए-सी]

1.4 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहले उत्तरदाता ने **25.09.2006** दिनांकित संचार को संबोधित किया था। यह भी निर्विवाद है कि आई. ओ. सी. के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि पहले प्रतिवादी को नोटिस को नोटरी करना चाहिए। इस संबंध में एक बैठक हुई। नोटिस नोटराइज्ड किया गया और इसके अलावा, **16.11.2006** पर प्राप्त किया गया। दिनांक **25.09.2006** के नोटिस को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पहले प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि उसने यह बताया है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेंगलूर में स्थानांतरित हो गए हैं, इससे भी अधिक, वे डीलरशिप की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। वे "डीलरशिप से हटना और नए आर.ओ. नियुक्त करना चाहते थे।" डीलर समझौते के अनुसार तीन महीने पहले। दूसरे शब्दों में, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं हो सकता कि पहले प्रतिवादी ने वास्तव में खंड (3) का इस्तेमाल किया है। प्रयुक्त शब्द अशोभनीय प्रतीत हो सकते हैं। हालाँकि, आचरण इसमें कोई संदेह नहीं है, और इससे भी अधिक, यहां तक कि पहले प्रतिवादी के पास भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि कार्रवाई खंड (3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। तीन महीने की समाप्ति पर, खंड (3) में प्रदान किए गए कठोर परिणाम सामने आएंगे। हालाँकि, चूँकि यह इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि **IOC** ने नोटिस को फल देने के लिए **18.11.2006** को अपनी सहमति दी होगी, **IOC** द्वारा दायर अपील में दूसरे अपीलकर्ता ने **03.10.2006** के नोटरीकृत पत्र का उल्लेख किया था जो था **16.11.2006** को प्राप्त हुआ। आईओसी ने डीलरशिप से इस्तीफा देने के पहले प्रतिवादी के इरादे पर ध्यान दिया है। इसके बाद, पहले प्रतिवादी से व्यवस्था होने तक काम जारी रखने

का अनुरोध किया गया। अंत में, पत्र आईओसी के साथ पहले प्रतिवादी के जुड़ाव के लिए आभार व्यक्त करने और दोनों भागीदारों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देने के साथ समाप्त होता है। पत्र की शर्तों और लहजे और परिस्थितियों से, मध्यस्थ, जो तथ्यों और गुणों के आधार पर चुना गया न्यायाधीश है, ने निष्कर्ष निकाला कि नोटिस की स्वीकृति थी। इस पर बहस हो सकती है कि क्या स्वीकृति की पर्याप्त अभिव्यक्ति थी। "हमारी डीलरशिप से इस्तीफा देने के आपके इरादे पर ध्यान दिया गया है" जैसे शब्दों को शायद दूरदर्शिता के लाभ के साथ अलग-अलग शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सकता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पत्र को समग्र रूप से तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, विशेष रूप से, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मध्यस्थ के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रकाश में, तो उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की है। खंड (3) किसी भी पक्ष को अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने की अनुमति देता है। तीन महीने का नोटिस देकर, यदि नोटिस आईओसी का है, तो आईओसी व्यवस्था करने में सक्षम है ताकि डीलर द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं में अचानक व्यवधान न हो। एक व्यापारी द्वारा प्रदान किए जाने पर अचानक व्यवधान नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह, आईओसी द्वारा समाप्ति से डीलर सतर्क हो जाएगा और वह अपने मामलों को निष्पक्ष तरीके से व्यवस्थित करने की दिशा में उचित कदम उठा सकता है। [पैरा 21][697-सी-एच; 698-ए-सी]

1.5 इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि उपरोक्त अर्थ में समझौते की समयपूर्व समाप्ति के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी, तथ्यों में मध्यस्थ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को विकृत नहीं माना जा सकता है। यह निस्संदेह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। इससे अदालत के हस्तक्षेप का दरवाजा बंद हो जाता है। मध्यस्थ के निष्कर्ष को "पेटेंट अवैधता" को धोखा देने वाला नहीं कहा जा सकता। [पैरा 22][698-डी-ई]

1.6 उच्च न्यायालय ने "समझौते की समाप्ति" और "डीलरशिप से इस्तीफा" के बीच अंतर निकालने के लिए विज्ञापन दिया। उच्च न्यायालय भी इस आधार पर आगे बढ़ा कि चूंकि समझौता पहले प्रतिवादी को मामला वापस लेने से नहीं रोकता है, इसलिए मामले का अनुबंध अधिनियम के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए एक योग्यता समीक्षा की गई कि पहले प्रतिवादी के 'इस्तीफे' के प्रस्ताव को पत्र दिनांक **22.11.2006** द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। [पैरा 23][698-ई-एफ]

1.7 विचाराधीन खंड में डीलरशिप से त्यागपत्र देने का प्रावधान नहीं है। दरअसल, यह केवल समझौते को समाप्त करने का प्रावधान करता है। पहले प्रतिवादी ने पत्र दिनांक **25.09.2006** में जो संकेत दिया है, जिसकी सामग्री को नोटरीकृत संस्करण दिनांक **03.10.2006** में दोहराया गया है और **16.11.2006** को दूसरे अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है, वह यह है कि पहला प्रतिवादी इससे 'वापस ले रहा' था। डीलरशिप. इस आधार पर उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं किया जा सकता कि विचाराधीन खंड में इस्तीफे पर विचार नहीं किया गया है। वास्तव में, हालांकि सभी मामलों में नहीं, नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही इस्तीफा प्रभावी हो सकता है। दूसरी ओर, खंड (3) में जिस

बात पर विचार किया गया है वह किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए तीन महीने का नोटिस है। [पैरा 24][698-एफ-एच]

1.8 यह बताया गया कि आईओसी प्रबंधन द्वारा स्वीकृति वास्तव में **07.12.2006** को हुई थी न कि **22.11.2006** को। हालाँकि, दिनांक **18.11.2006** के संचार के आलोक में, अनिवार्य रूप से मान्यता देना और संक्षेप में स्वीकृति या अनुमोदन बताना; पहला प्रतिवादी उसी से ताकत नहीं ले सकता **IOC** का मामला है कि डीलरशिप को फिर से देने के मामले में मामले को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक **07.12.2006** को निर्णय लिया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निकासी वापस लेने के लिए संचार पहले प्रतिवादी द्वारा **11.12.2006** को दिया गया था जो **07.12.2006** के बाद है। [पैरा 2] [699-ए; 699-ई-एफ]

1.9 इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि स्वीकृति आवश्यक है, उच्च न्यायालय ने धारा **37** के तहत एक कार्यवाही में मध्यस्थ के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अवैध रूप से कार्य किया और इससे भी अधिक, एक निष्कर्ष धारा **34** के तहत जिला न्यायाधीश को स्वीकार्य पाया गया कि स्वीकृति थी पत्र दिनांक **18.11.2006**। [पैरा 26][699-जी-एच]

1.10 उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द करने के बाद पहले प्रतिवादी को डीलरशिप की बहाली का आदेश देने और नुकसान का दावा करने के लिए इसे पहले प्रतिवादी के लिए खुला छोड़ कर आगे बढ़ने में भी गलती की। न्यायालय, पुरस्कार को रद्द करने के बाद, पुरस्कार को संशोधित करके आगे राहत देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसे पार्टियों को किसी दिए गए मामले में अपने उपचार पर काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही यह उचित रूप से पुरस्कार में हस्तक्षेप करता हो। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और पुरस्कार बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 27,28] [700-ए-सी]

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 ई और 220 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम. हकीम और अन्य (2021) 9 एससीसी 1- पर भरोसा किया।

सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एससीआर 522; पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और अन्य बनाम रमेश कुमार एंड कंपनी और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056 - संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 7 एससीआर 522 संदर्भित किया गया है पैरा 14

(2021) 9 एससीसी 1 पर भरोसा किया पैरा 27

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील 2023 के No.3533

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.01.2021 से
2011 के एमएफए नंबर 4450 में बेंगलुरु में कर्नाटक के।

साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 3534

देवदत्त कामत, वरिष्ठ वकील, निशांत पाटिल, आयुष पी शाह, हर्ष पांडे, रेवंता सोलंकी, विक्रम मेहता, सुश्री राशि राम पाल, विकास मेहता, अपीलकर्ताओं के वकील।

शैलेश मडियाल, राजन परमार, विनायक एस पंडित, सुश्री राखी एम, अक्षय कुमार, सुश्री दिविजा महाजन, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।
2. 2021 के एसएलपी (सी) 5698 से उत्पन्न सिविल अपील में, अपीलकर्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (इसके बाद संक्षेप में "आईओसी" के रूप में संदर्भित), प्रथम अपीलकर्ता, बेंगलोर के मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबंधक और हैं। मैंगलोर डिवीजन के मुख्य डिवीजनल खुदरा बिक्री प्रबंधक। उक्त अपील में दूसरी प्रतिवादी एक श्रीमती हैं। एमपी। पार्वती, जिसे नए डीलर के रूप में जाना जाता है, जो अन्य अपील में अपीलकर्ता है, अर्थात् एसएलपी (सी) 5591 ओएफ 2021 से उत्पन्न सिविल अपील।

तथ्य

3. 31.10.2003 को, IOC ने पेट्रोल/HSD पंप डीलर के साथ अनुबंध किया प्रथम प्रतिवादी के साथ समझौता. अनुबंध का खंड (3) पढ़ा गया निम्नलिखित नुसार:

“(3) यह समझौता 13 अक्टूबर 2003 के दिन से पंद्रह वर्ष के लिए लागू रहेगा और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की क्रमिक अवधि के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर निर्धारित न कर दे। समझौता और ऐसे किसी भी नोटिस की समाप्ति पर यह समझौता और पूर्वोक्त रूप से दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की समाप्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात किसी भी मामले के संबंध में दूसरे के खिलाफ किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। या इस तरह की समाप्ति से पहले

की बात, बशर्ते कि इस खंड में शामिल कुछ भी इस समझौते के खंड 56 में उल्लिखित घटनाओं के घटित होने पर इस समझौते को पहले समाप्त करने के निगम के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

4. 25.09.2006 को, पहले प्रतिवादी ने निम्नलिखित को संबोधित किया दूसरे अपीलकर्ता को संचार:

दिनांक 31.10.2003

को,

मुख्य संभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विपणन प्रभाग, बेंगलूर प्रभागीय कार्यालय,

इंडियन ऑयल भवन #29,

पी. कलिंगा राव रोड, (मिशन रोड)

बेंगलूर - 560027.

प्रिय महोदय,

विषय: आर.ओ. से आहरण के साथ। डीलरशिप

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक BD0/242 दिनांक 23 अक्टूबर, 2003

उपरोक्त विषय के संदर्भ में हम आर.ओ. को चलाने के लिए इतने वर्षों तक हमें समर्थन और सहयोग देने के लिए आपके और आईओसी परिवार के सदस्यों के बहुत आभारी हैं।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेंगलूर चले गए हैं। इसलिए, हम आर.ओ. की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, कृपया आर.ओ. से हट जाएं। डीलरशिप और नए आर.ओ. की नियुक्ति हमारे समझौते के अनुसार तीन महीने पहले डीलर दिनांक: 31 अक्टूबर 2003।

आशा है आप हमारे विनम्र अनुरोध पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी

श्री सत्यनारायण स्वामी सेवा स्टेशन के लिए

(पी. एस. सुरेश)

(ज्योति सुरेश)

सहभागी

सहभागी

सी.सी. से:बिक्री अधिकारी मैसूर

// सही टाइप प्रतिलिपि //

5. इसमें कोई विवाद नहीं है कि 30.09.2006 को एक शारीरिक बातचीत हुई थी जिसके दौरान आईओसी ने जोर देकर कहा था कि पहले प्रतिवादी के अनुरोध को नोटरीकृत किया जाए। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 25.09.2006 के पत्र का नोटरीकृत संस्करण 16.11.2006 को प्राप्त हुआ था। इसे स्पष्ट रूप से पहले 3.10.2006 को नोटरीकृत किया गया था। दूसरे अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.11.2006 को एक उत्तर भेजा गया था। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

22 नवंबर, 2006

रेग. पोस्ट ए. ओ.

श्री. पी. एस. सुरेश और श्रीमती ज्योति सुरेश पार्टनर

श्री. सत्यनारायणस्वामी सर्विस स्टेशन

मैसूर-बंटवाल रोड

पेरियापटना 5 71107

मैसूर जिला

प्रिय महोदय

विषय: डीलरशिप से इस्तीफा

यह हमारे कार्यालय को 16 नवंबर 2006 को प्राप्त 3 अक्टूबर 2006 के नोटरीकृत पत्र का संदर्भ है, जिसमें हमें हमारे रिटेल आउटलेट डीलरशिप से सेवानिवृत्त होने के आपके इरादे के बारे में सूचित किया गया था।

आपके द्वारा भेजा गया यह नोटरीकृत पत्र, संदर्भ बीडीओ: 242 दिनांक 23.10.2003 के माध्यम से हमारे द्वारा आपको भेजे गए मान्यता पत्र के संदर्भ में है, साथ ही डीलरशिप समझौते के साथ आप दोनों को पेरियापटना में हमारे 'ए' साइट रिटेल आउटलेट के डीलरों के रूप में मान्यता दी गई है। आपके द्वारा मैसर्स नाम और शैली के तहत चलाया जाता है। सत्यनारायणस्वामी सर्विस स्टेशन।

जैसा कि आपके पत्र में कहा गया है, हमने हमारी डीलरशिप से इस्तीफा देने के आपके इरादे पर ध्यान दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब तक हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक परिचालन जारी रखें।

हमारे संगठन के साथ आपके जुड़ाव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आप दोनों को आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

भारतीय तेल निगम लिमिटेड के लिए

सैमसन चाको

मुख्य प्रभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक

// सही टाइप प्रतिलिपि //

6. इसके बाद, हमें उनकी ओर से 11.12.2006 दिनांकित पत्र पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे अपीलार्थी के लिए प्रथम प्रत्यर्थी। यह इस प्रकार है

तारीख: -11-12-2006

को,

मुख्य संभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विपणन प्रभाग, बेंगलोर प्रभागीय कार्यालय,

इंडियन ऑयल भवन #29,

पी. कलिंगा राव रोड, (मिशन रोड)

बेंगलुरु.

प्रिय महोदय,

मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने आर.ओ. भेज दिया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डीलरशिप निकासी पत्र (नोटरीकृत)।

लेकिन मैं डीलरशिप से निकासी वापस लेना चाहता हूं। मुझे हुई परेशानी और असुविधा के लिए बेहद खेद है।

लेकिन मैं आपको आश्चस्त करूंगा सर, कि भविष्य में हम आपको कोई परेशानी दिए बिना आउटलेट को सुचारु रूप से चलाएंगे।

आशा है आप मेरे विनम्र अनुरोध पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी

सीसी: - बिक्री अधिकारी को,

मैसूर,

सत्यनारायण स्वामी सर्विस स्टेशन के लिए

भागीदार

// सही टाइप प्रतिलिपि //

7. 21.12.2006 पर, हम निम्नलिखित संचार को संबोधित पाते हैं आई. ओ. सी. की ओर से पहले प्रत्यर्थी के लिए दूसरा अपीलकर्ता:

"आरपीएडी द्वारा

21 दिसंबर, 2006

एमआईएस. श्री सत्यनारायणस्वामी सर्विस स्टेशन

इंडियन ऑयल डीलर

मैसूर-बंटवाल रोड पेरियापटना-571107।

मैसूर जिला।

प्रिय महोदय,

उप: इस्तीफा वापस लेना

हमारे पास 18/12/2006 के विषय पर आपके पत्र का संदर्भ है, जिसमें हमारे डीलरशिप से आपका इस्तीफा वापस लिया गया है।

आपने शुरू में 25/09/2006 पर अपना इस्तीफा दे दिया था। 30/09/2006 को अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा एक बार फिर आपके साथ इसकी पुष्टि की गई थी। आपकी पुष्टि पर, आपको एक नोटरीकृत त्याग पत्र जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, आपने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, और एक बार फिर 16.11.2006 पर, आपने 03/10/2006 पर विधिवत नोटरीकृत एक त्याग पत्र प्रस्तुत किया।

उपरोक्त की प्राप्ति पर, हमने आपको आर. पी. ए. डी. द्वारा आपका इस्तीफा स्वीकार करते हुए एक पत्र भेजा। इसके बाद आप 22/11/2016 पर हमारे कार्यालय गए। अपने पिता के साथ, जिसमें आपने एक बार फिर इस्तीफा देने के अपने फैसले को बरकरार रखा क्योंकि आप वर्तमान में बेंगलोर में बसे हुए थे और आप पेरियापटना में अपने आरओ में ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। यह आपके पिता के आपके दृष्टिकोण के विरोध के बावजूद था।

आपके नोटरीकृत इस्तीफे और व्यक्तिगत पुष्टि के आधार पर, हमने आपके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए अपने प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त कर ली है। त्यागपत्र दें। हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि उपरोक्त कारणों से इस्तीफे को वापस लेने के आपके अनुरोध पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी

भारतीय तेल निगम लिमिटेड के लिए

(सैमसन चाको)

मुख्य प्रभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक.

// सही टाइप प्रतिलिपि //

8. आई. ओ. सी. ने 23.12.2006 पर पेट्रोलियम आउटलेट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद, 28.12.2006 को नए डीलर को डीलरशिप प्रदान की गई। पहले प्रतिवादी द्वारा आईओसी, कर्नाटक के महाप्रबंधक के समक्ष अपील की गई थी। अपील 02.04.2007 को खारिज कर दी गई। इसके चलते मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया। दिनांक 15.01.2009 के निर्णय द्वारा एकमात्र मध्यस्थ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि "क्योंकि आईओसी और उसके अधिकारियों ने अपने पत्र दिनांक 22.11.2006 के माध्यम से डीलरशिप के दावेदार के इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में सूचित किया था, जिससे दोनों पक्षों के बीच अनुबंध समाप्त हो गया , इस्तीफा वापस लेने के लिए दावेदार के दिनांक 11.12.2006 के बाद के अनुरोध को अस्वीकार करना कानून के अनुसार था। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या दिनांक 11.12.2006 के पत्र द्वारा डीलरशिप से इस्तीफा वापस लेने में प्रथम प्रतिवादी की कार्रवाई कानून के अनुसार थी, यह पाया गया कि इस्तीफे की स्वीकृति 22.11.2006 को सूचित कर

दी गई थी। पहले प्रतिवादी का पीछे हटने का कदम कानून के अनुरूप नहीं था। इस मुद्दे के संबंध में कि क्या पहले प्रतिवादी ने समझौते के ज्ञापन के खंड (3) में निर्धारित समय के भीतर इस्तीफे की सूचना वापस ले ली थी, यह इस प्रकार पाया गया:

“समझौते के ज्ञापन के खंड 3 में विशेष रूप से इस्तीफा वापस लेने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अनुबंध में उल्लिखित 3 महीने की नोटिस अवधि केवल बाहरी सीमा है, जिस समय तक नोटिस प्राप्त करने वाले पक्ष को अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। नोटिस अवधि के दौरान किसी भी समय, प्राप्तकर्ता पक्ष स्वीकृति व्यक्त कर सकता है जिससे पार्टियों के बीच अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि किसी प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति की सूचना से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। चूंकि उत्तरदाताओं ने अपने दिनांक 22.11.2006 के पत्र के माध्यम से दावेदार के इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में सूचित किया है, इसलिए दावेदार का दिनांक 11.12.2006 का अगला पत्र जिसमें त्याग पत्र वापस लेने का अनुरोध किया गया है, कानून के अनुसार नहीं है। इसलिए इस मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं है कि क्या दावेदारों ने समय सीमा के भीतर अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।

(जोर दिया गया)

9. मध्यस्थ ने आगे पाया कि नए डीलर के पक्ष में जारी किया जा रहा आशय पत्र त्रुटिपूर्ण नहीं था। अन्य सभी मुद्दों का उत्तर देते हुए, जिनके लिए हमें पहले प्रतिवादी के खिलाफ हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, पुरस्कार पारित किया गया। पहले प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत प्रधान और सत्र न्यायाधीश, मैसूर के दरवाजे खटखटाए। अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता मुकदमा खारिज कर दिया गया।

10. पहले प्रतिवादी द्वारा की गई अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुरस्कार और धारा 34 के तहत अदालत द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहले प्रतिवादी को बहाल किया जाएगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर डीलरशिप, ऐसा न करने पर पहले प्रतिवादी को निर्णय के निष्पादन की मांग करने और आईओसी और उसके अधिकारियों से आवश्यक हर्जाना मांगने का हकदार माना गया।

11. यह वह निर्णय है जिसके कारण दो अपीलें दायर की गईं। आईओसी और उसके अधिकारियों के अलावा, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, नए डीलर, अर्थात्, एम.पी. दूसरी अपील पार्वती ने दायर की है।

12. हमने आईओसी द्वारा दायर अपील की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विक्रम मेहता को सुना। हमने नए डीलर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामथ को भी सुना। इसके बाद, हमने पहले प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील श्री शैलश मडियाल को सुना।

13. आई. ओ. सी. के विद्वान वकील श्री विक्रम मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को पलटने के मामले में निर्णयों के एक समूह द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। वह हमें पत्राचार और पहले प्रतिवादी के आचरण पर भी ले गए, यह तर्क देने के लिए कि पहला प्रतिवादी अनुबंध को समाप्त करना चाहता था, जैसा कि दिनांकित 25.09.2006 नोटिस भेजकर स्वयं स्पष्ट है। यह बताए जाने पर कि संचार नोटरीकृत होना चाहिए, इसे 03.10.2006 पर नोटरीकृत किया गया था और इसे दूसरे अपीलार्थी द्वारा 16.11.2006 पर प्राप्त किया गया था। इसे 18.11.2006 पर भी स्वीकार किया गया था। मध्यस्थ ने उपरोक्त पंक्तियों पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं। यह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। जिला न्यायाधीश ने धारा 34 के तहत कार्यवाही में पुरस्कार को अभेद्य पाया था। इसलिए, एक अलग दृष्टिकोण के संभव होने पर भी, उच्च न्यायालय ने पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में अवैध रूप से काम किया। वास्तव में, वह प्रस्तुत करेंगे कि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वास्तव में सही दृष्टिकोण था। प्रथम उत्तरदाता के भागीदारों के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त करने वाले शब्दों की अभिव्यक्ति। पत्र 18.11.2006 में अंतिम पैराग्राफ के अलावा पहले प्रतिवादी के भागीदारों के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त करने वाले शब्दों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय कानून के सिद्धांतों को लागू करने के लिए आगे बढ़ा है जो संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि मध्यस्थ के निष्कर्षों को निश्चित रूप से विकृत नहीं कहा जा सकता। वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने न केवल पुरस्कार को रद्द करने में, बल्कि पुरस्कार को संशोधित करने के लिए आगे बढ़कर स्पष्ट रूप से अवैध रूप से काम किया है, जो पूरी तरह से उसकी शक्ति से परे है। दूसरे शब्दों में, वह उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रतिवादी को डीलरशिप बहाल करने के निर्देश को स्पष्ट रूप से अवैध बताएँगे।

14. नए डीलर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत प्रस्तुत करेंगे कि पहले प्रतिवादी द्वारा किए गए आचरण और पत्राचार से पता चलता है कि यह सावधानीपूर्वक सोचा गया था। दूसरे शब्दों में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई जबरदस्ती या अन्य खराब तत्व था जिसने भागीदारों को खंड (3) लागू करने के लिए प्रेरित किया। वह सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करेंगे। इसमें उन्होंने निम्नलिखित कथन पर जोर दिया:

“40. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28(3) में किया गया परिवर्तन वास्तव में एसोसिएट बिल्डर्स में पैरा 42.3 से 45 में बताए गए अनुसार है [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सिव) 204] , अर्थात्, अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को निर्णय लेने के लिए होता है, जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि कोई भी निष्पक्ष दिमाग वाला या उचित व्यक्ति नहीं करेगा; संक्षेप में, मध्यस्थ का दृष्टिकोण अपनाना संभव भी नहीं है। इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध के बाहर घूमता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। चुनौती का यह आधार अब धारा 34(2-ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के अंतर्गत आएगा।”

15. इसके बाद, उन्होंने हमारा ध्यान पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और अन्य बनाम रमेश कुमार एंड कंपनी और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया।

"12. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती को खारिज करने में 1996 अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के विपरीत काम किया था। ऐसा करने में अपनी विफलता के अलावा, उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दावे को पूरी तरह से डिक्री करने के जिला न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया। यह अभ्यास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। मध्यस्थ पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथ्य के प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने का हकदार था। मध्यस्थ निर्णय में बिल्कुल यही किया गया था। मध्यस्थ के फैसले को उत्तरदाताओं द्वारा 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत असफल रूप से चुनौती दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने और, जैसा कि हमने पहले नोट किया है, दावे पर फैसला सुनाकर एक कदम आगे बढ़ने का कोई कानूनी आधार नहीं था।"

16. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि समझौते के खंड (3) का उद्देश्य उस पक्ष को लाभ देना था जिसे पत्र भेजा गया था। अनुबंध को समाप्त करते हुए भेजा जाता है। मध्यस्थ द्वारा अनुबंध का निर्माण उस अंक पर हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं है जो अदालत को गलत लगता है। फिर भी विवादित फैसले में ठीक यही किया गया है। वह बताएगा कि, वास्तव में, नया व्यापारी एक शहीद की पत्नी है जो एक मारे गए सैनिक की विधवा है।

17. विद्वान वकील श्री शैलेश मडियाल ने निम्नलिखित तरीके से अपीलार्थियों का प्रतिवाद करने का प्रयास किया: उन्होंने कहा कि वास्तव में, विचाराधीन समझौते के खंड (3) में स्पष्ट रूप से विचार किया गया था कि डीलरशिप को 15 साल की अवधि के लिए पवित्र रहना था। यह केवल खंड (56) में अनुध्यात पूर्व समाप्ति के अधीन है। खंड (56), यह इंगित किया गया है, आई. ओ. सी. द्वारा कुछ अधिनियमों और चूक पर समाप्ति के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पहले 15 वर्षों की समाप्ति के बाद ही पक्षों ने अनुबंध को एक बार में 5 साल बढ़ाने पर विचार किया। अनुबंध की कुल अवधि शुरू में 15 साल है और बाद में 5 साल के विस्तार के आधार पर, प्रत्येक 30 साल तक जा सकता है। हालांकि, पहले 15 वर्षों के दौरान लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर डीलरशिप को समाप्त करने की सुविधा की अनुमति नहीं थी। वह प्रस्तुत करेंगे कि इस तरह की व्याख्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिसने एक बड़ी राशि का निवेश किया होगा, वह आई. ओ. सी. द्वारा केवल तीन महीने की अवधि का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने की शक्ति से संपन्न होने से डीलरशिप खो देगा। चूंकि इस मामले में नोटिस पहले 15 वर्षों के भीतर भेजा गया था, खंड (3) लागू नहीं था, और कानून में कोई समाप्ति नहीं थी। विद्वान वकील इस बात से सहमत थे कि इस तरह का विवाद कभी नहीं उठाया गया था मध्यस्थ, जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष। इसके बाद, उन्होंने तर्क दिया कि कथित स्वीकृति दिनांक 28.11.2006 स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्वीकृति से पहले, जो वे बताते

हैं, प्रबंधन द्वारा केवल 07.12.2006 पर हुई थी, पहले प्रतिवादी ने पहले के संचार को वापस ले लिया था। वह प्रस्तुत करेंगे कि मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अपीलार्थियों की शिकायत के संबंध में कि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को संशोधित करके अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्य करते हुए अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, वह बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उक्त विवाद में योग्यता हो सकती है।

विश्लेषण

18. विवाद खंड (3) के इर्द-गिर्द घूमता है जो हमारे पास पहले से स्थापित। हमें इस मामले में इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि हम पहले प्रतिवादी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दे सकते कि डीलरशिप के पहले 15 वर्षों के दौरान तीन महीने का नोटिस देकर डीलरशिप को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या मध्यस्थ के विचार के लिए नहीं रखी गई थी। इसे जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया जाता है। पहला उत्तरदाता कॉल कर रहा है इस न्यायालय पर अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले में पूरी तरह से नई व्याख्या करने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रचार किया गया विवाद ही एकमात्र संभव दृष्टिकोण है। वास्तव में, पहले प्रत्यर्थी का आचरण उस व्याख्या पर आधारित होता है जो विक्रेता के पहले 15 वर्षों के भीतर भी तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने के लिए पक्षों के लिए खुला छोड़ देता है।

19. खंड (3) को पढ़ने पर, वास्तव में, इस न्यायालय को यह पता चला कि यहां एक अनुबंध में एक शर्त है जिसमें स्पष्ट रूप से तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। . हम इस खंड को इस अर्थ में तोड़ देंगे कि इसमें समझौते को समाप्त करने के इरादे से दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष (अनुबंध से हटाए गए शब्द) द्वारा समझौते के निर्धारण पर विचार किया गया है। इसके बाद, खंड में यह प्रावधान है कि इस तरह के नोटिस की समाप्ति पर, समझौता और दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कोई भी शब्द नहीं हैं जो समझौते के निर्धारण के लिए समझौते को समाप्त करने के इरादे की सूचना को अपरिहार्य मानने का सुझाव देते हों। नोटिस जारी होने से गेंद घूमती है और प्रक्रिया सफलतापूर्वक समझौते में समाप्त होती दिखाई देती है और समझौते के तहत दिया गया लाइसेंस रद्द या रद्द कर दिया जाता है।

20. हालांकि इस तरह का दृष्टिकोण समझौते का सही निर्माण प्रतीत होता है, पहले प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री शैलेश मडियाल इंगित करेंगे कि आई. ओ. सी. और इससे भी अधिक, मध्यस्थ, और इसलिए जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी इस आधार पर आगे बढ़ें हैं कि केवल समाप्ति की सूचना की स्वीकृति ही पर्याप्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है, हम इस मामले पर इस आधार पर विचार करेंगे कि स्वीकृति आवश्यक है।

21. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने क्या संबोधित किया संचार दिनांक 25.09.2006. यह भी निर्विवाद है कि आईओसी के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पहले प्रतिवादी को नोटिस को नोटरीकृत करना होगा। इस संबंध में एक बैठक भी हुई। नोटिस नोटरीकृत किया गया और इससे भी अधिक, 16.11.2006 को प्राप्त हुआ। दिनांक 25.09.2006 के नोटिस का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पहले प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि उसने यह बताया है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेंगलोर में स्थानांतरित हो गए हैं, और इससे भी अधिक, वे डीलरशिप की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। "डीलरशिप से हटना और नए आर.ओ. नियुक्त करना चाहते थे।" हमारे समझौते के अनुसार तीन महीने पहले डीलर दिनांक: 13 अक्टूबर 2003।" दूसरे शब्दों में, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं हो सकता कि पहले प्रतिवादी ने वास्तव में खंड (3) का इस्तेमाल किया है। प्रयुक्त शब्द अशोभनीय प्रतीत हो सकते हैं। हालाँकि, जैसा कि देखा गया आचरण हमें कोई संदेह नहीं देता है, और इससे भी अधिक, यहां तक कि पहले प्रतिवादी के पास भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि कार्रवाई खंड (3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। तीन महीने की समाप्ति पर, खंड (3) में प्रदान किए गए कठोर परिणाम सामने आएंगे। हालाँकि, चूँकि हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि IOC ने 18.11.2006 को नोटिस को फलित करने के लिए अपनी सहमति दी होगी, IOC द्वारा दायर अपील में दूसरे अपीलकर्ता ने 03.10.2006 को नोटरीकृत पत्र का उल्लेख किया था जो प्राप्त हुआ था 16.11.2006. आईओसी ने डीलरशिप से इस्तीफा देने के पहले प्रतिवादी के इरादे पर ध्यान दिया है। इसके बाद, हम ध्यान दे सकते हैं कि पहले प्रतिवादी से व्यवस्था होने तक संचालन जारी रखने का अनुरोध किया गया था। अंत में, पत्र के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होता है प्रथम प्रतिवादी का आईओसी के साथ जुड़ाव और दोनों को शुभकामनाएं अपने भविष्य के प्रयासों में सर्वोत्तम भागीदार बनें। शर्तों से और पत्र का लहजा और परिस्थितियाँ, मध्यस्थ कौन है चुने गए न्यायाधीश ने तथ्यों और गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। यह बहस के लिए खुला हो सकता है कि क्या वहाँ था स्वीकृति की पर्याप्त अभिव्यक्ति. "हमने हमारी डीलरशिप से इस्तीफा देने के आपके इरादे पर ध्यान दिया है" जैसे शब्दों को शायद दूरदर्शिता के लाभ के साथ अलग-अलग शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सकता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पत्र को समग्र रूप से तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, विशेष रूप से, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मध्यस्थ के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रकाश में, तो हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट गलती की है। खंड (3) किसी भी पक्ष को अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने की अनुमति देता है। तीन महीने का नोटिस देकर, यदि नोटिस प्राप्तकर्ता आईओसी है, तो आईओसी व्यवस्था करने में सक्षम है ताकि डीलर द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं में अचानक व्यवधान न हो। दूसरे शब्दों में, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह, आईओसी द्वारा समाप्ति से डीलर सतर्क हो जाएगा और वह अपने मामलों को निष्पक्ष तरीके से व्यवस्थित करने की दिशा में उचित कदम उठा सकता है।

22. इसलिए, उपरोक्त अर्थ में इस आधार पर आगे बढ़ना समझौते की समयपूर्व समाप्ति के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि तथ्यों में मध्यस्थ द्वारा लिया गया

दृष्टिकोण, विकृत होने के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। यह निस्संदेह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। इससे अदालत के हस्तक्षेप का दरवाजा बंद हो जाता है। मध्यस्थ के निष्कर्ष को "पेटेंट अवैधता" को धोखा देने वाला नहीं कहा जा सकता।

23. उच्च न्यायालय ने एक ड्रा निकालने के लिए विज्ञापन देकर कार्यवाही की है "अनुबंध की समाप्ति" और "डीलरशिप से इस्तीफा" के बीच अंतर। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर भी कार्यवाही की है कि चूंकि समझौता पहले प्रतिवादी को मामला वापस लेने से नहीं रोकता है, इसलिए मामले का अनुबंध अधिनियम के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए एक योग्यता समीक्षा की गई कि पहले प्रतिवादी के 'इस्तीफे' के प्रस्ताव को पत्र दिनांक 22.11.2006 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

24. यह सच हो सकता है कि विचाराधीन खंड में डीलरशिप से इस्तीफे का प्रावधान नहीं था। दरअसल, यह केवल समझौते को समाप्त करने का प्रावधान करता है। पहले प्रतिवादी ने पत्र दिनांक 25.09.2006 में जो संकेत दिया है, जिसकी सामग्री को नोटरीकृत संस्करण दिनांक 03.10.2006 में दोहराया गया है और 16.11.2006 को दूसरे अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है, वह यह है कि पहला प्रतिवादी इससे 'वापस ले रहा' था। डीलरशिप. हम इस आधार पर उच्च न्यायालय का समर्थन करने में असमर्थ हैं कि विचाराधीन खंड में इस्तीफे पर विचार नहीं किया गया है। वास्तव में, हालांकि सभी मामलों में नहीं, नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही इस्तीफा प्रभावी हो सकता है। दूसरी ओर, खंड (3) में जिस बात पर विचार किया गया है वह किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए तीन महीने का नोटिस है।

25. श्री शैलेश मडियाल ने बताया कि आई. ओ. सी. का प्रबंधन वास्तव में 07.12.2006 पर हुआ था न कि 22.11.2006, यह सच है कि अभिवचन में (धारा 34 के तहत कार्यवाही में जिला न्यायालय के समक्ष), यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है:

“4. प्रतिवादियों द्वारा इस्तीफा प्रस्तुत करने के बाद दावेदारों से नोटोरिज्ड पत्र की प्राप्ति पर डीलरशिप को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, जिसे 07.12.06 को आईओसी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था और वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए रिटेल आउटलेट को संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करनी थी। निगम का और बड़े पैमाने पर जनता को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति को भी ध्यान में रखना।

“5. डीलर ने 25.09.2006 को डीलरशिप वापस लेने का अनुरोध किया है। जैसा कि पहले के पैराग्राफ में कहा गया है, जो कुख्यात पत्र के आधार पर दिनांक 25.09.2006 के पत्र में कही गई बातों को पुष्ट करता है। इस प्रतिवादी ने 07.12.2006 को डीलरशिप समाप्त करने के लिए प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त कर ली है और दिनांक 21.12.06 को पत्र के माध्यम से उत्तर भी दिया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि डीलर के वापसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। डीलरशिप समझौते के खंड 3 के

अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे के पत्र को अस्वीकार करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से कोई दायित्व नहीं है।

हालाँकि, दिनांकित 18.11.2006 के संचार के प्रकाश में, अनिवार्य रूप से स्वीकृति को पहचानना और सार में व्यक्त करना या अनुमोदन; पहला उत्तरदाता उसी से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। आई. ओ. सी. के पास एक मामला है कि डीलरशिप को फिर से देने के मामले में मामले को आगे बढ़ाने के लिए 07.12.2006 दिनांकित निर्णय लिया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निकासी को वापस लेने का आशय रखने वाला संचार पहले उत्तरदाता द्वारा 11.12.2006 पर दिया गया था जो 07.12.2006 के बाद है।

26. इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि स्वीकृति आवश्यक है, हम हैं इस विचार से कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 के तहत एक कार्यवाही में मध्यस्थ के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अवैध रूप से काम किया और इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश को स्वीकार्य पाया गया कि दिनांकित 18.11.2006 पत्र के माध्यम से स्वीकृति थी।

27. उच्च न्यायालय ने भी बहाली का आदेश देने में गलती की पुरस्कार को अलग रखने के बाद पहले प्रतिवादी को डीलरशिप का अधिकार और इसे दावा करने वाले पहले प्रतिवादी के लिए खुला छोड़कर आगे बढ़ें नुकसान यह किसी भी संदेह से परे है कि न्यायालय, पुरस्कार को रद्द करने के बाद, पुरस्कार को संशोधित करके आगे राहत देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसे पार्टियों को किसी दिए गए मामले में अपना उपचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही यह उचित रूप से पुरस्कार में हस्तक्षेप करता हो इस संबंध में परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 ई और 220 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम. हकीम और अन्य।

28. अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिया जाएगा और पुरस्कार बहाल कर दिया जाएगा। पार्टियों को अपनी-अपनी लागत वहन करनी होगी।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

Translated and vetted by Kanwaljeet Singh Advocate (Chhattisgarh)